

D.P. ABHUSHAN LTD.

CIN No. L74999MP2017PLC043234

Date: July 04, 2020

To,
Listing Compliance Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C-1 Block-G,
Bandra Kurla Complex, Bandra,
Mumbai- 400 051, Maharashtra

Ref: D. P. Abhushan Limited (Security Code: DPABHUSHAN)

Subject: Intimation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015- Press Release

Respected Sir/Ma'am,
Please find enclosed herewith copy of the Press Release given in various English language and Hindi Language newspapers, relating to Proposal of Board of Directors for the Migration of Equity shares of the Company from SME Platform of NSE (NSE EMERGE) to Main Board of NSE in terms of Chapter IX of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 subject to necessary approvals.

Kindly take the same on record and please oblige us.

Thanking You,
For, **D. P. Abhushan Limited**

VIKAS
KATARIA

Digitally signed by
VIKAS KATARIA
Date: 2020.07.04
18:04:09 +05'30'

Vikas Kataria
Managing Director
DIN 02855136

Place: Ratlam

(टी।) प्रशासकीय स्तर पर ही इन प्रशासकीय कर्मियों को न्याय प्रदान करना है। विचार में परिवर्तन के अभाव में ही कर्मियों की सुविधाएँ हट गयीं। इन उन्हीं की सेवा मिली। इन योजनाओं का मुक्त रूप जानूँ तो मुझे भी किसी प्रकार का सम्मान प्राप्त कर लिये। मैं विचारपूर्वक सोच रहा हूँ। इन सब योजनाओं का अन्तर्गत रूप के लिए मैं हूँ। मैं योजना के अन्तर्गत दो के 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। इन योजना के लिए एक 10 करोड़ रुपये स्तर में खर्च हो रहा है। योजना के अन्तर्गत कर्मियों को एक लाख 65 रुपये में ही खर्च कर दिया जा रहा है।

सदस्यश्रीवरी, कुल, प्रस्तावक (सदस्य) भात येथील दस वृष प्रदेश के निव निवत अधिपेट नसरी, 119 इतरा राजस प्रथमरी सड भोवत-462023 वष. ये वृद्धि एव एत-1 ससुत नस्येनस निवे सडि नसरा वेवसु भोवत 462030 ये प्रसडिती सडसतन- भात येथली*, ससतिय सडसतन- इडिती येथली* सडसत पड ये सडसतरी के सडस के निव यीडसरी सड के सड सडिमेडर। सडस सडितीय सडसतन/सड यी/सडसत/1037/2016-2018 सडसत नसरी: 0755-4902729, 4362731 सडसतन: 8057078884 (सडि सडिडरी सड सडस येड भोवत येथी)। सडसत-11, सडसतरी सडस, सडसत ईमेल: yagzrakeshew@gmail.com

रोड़ रुपए का निवेश करेगी इंटेल

जियो प्लेटफॉर्म ने 12 निवेश से अब तक 1.17 लाख करोड़ रुपए जुटाए

आरआईएल ने जियो प्लेटफॉर्म की हिस्सेदारी बिक्री से 1,17,588.45 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह राशि 11 कंपनियों के 12 निवेश के जरिए जुटाई गई है। इसमें सबसे बड़ा निवेश फेसबुक का रहा है। फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में 9.99 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 43,573.62 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आरआईएल को अब तक जियो प्लेटफॉर्म की 25.09 हिस्सेदारी के लिए निवेश मिल चुका है। जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सब्सिडियरी है। यह कंपनी आरआईएल ग्रुप के डिजिटल बिजनेस एसेट्स जैसे रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जियो ऐप्स और हैप्टिक, रिवायर, फाईंड, नाउफ्लोट्स, हैथवे और डैन समेत कई अन्य एंटीटी में निवेश का संचालन करती है।

भारत को डिजिटल सोसायटी बनाने में मदद करेगी इंटेल: मुकेश अंबानी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि दुनिया के प्रौद्योगिकी लीडर्स के साथ हमारे संबंध गहरा होने पर हम बेहद खुश हैं। भारत को डिजिटल सोसायटी में बदलने के हमारे दृष्टिकोण को मूर्त रूप देने में ये हमारे सहायक हैं। इंटेल एक सच्चा इंडस्ट्री लीडर है, जो दुनिया को बदलने वाली तकनीक को बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इंटेल कैपिटल के पास अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों में एक मूल्यवान भागीदार होने का उत्कृष्ट रिकॉर्ड है।



भारत में डिजिटल परिवर्तन को ताकत देंगे: वेंडेल ब्रूक्स

इंटेल कैपिटल के अध्यक्ष वेंडेल ब्रूक्स ने कहा भारत में कम लागत वाली डिजिटल सेवाओं को ताकत देने के लिए जियो अपनी प्रभावशाली इंजीनियरिंग क्षमताओं का उपयोग कर रहा है। जीवन को समृद्ध बनाने के इंटेल के उद्देश्य के समरूप है। हमारा मानना है कि डिजिटल पहुंच और डेटा, व्यापार और समाज को बेहतर बना सकते हैं। निवेश से भारत में डिजिटल परिवर्तन को हम ताकत देंगे। नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो भारत को एक डिजिटल सोसायटी बनाने के काम में मदद कर रही है।



बहिष्कार का दिखा असर

हुआ देश का व्यापार घाटा कर 3.6 लाख करोड़ पर आया

डॉलर का आयात किया। कारोबारी साल 2018-19 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 53.56 अरब डॉलर था। 2017-18 में यह घाटा 63 अरब डॉलर था। सरकार चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करना चाहती है। इसके लिए उसने कई कदम भी उठाए हैं। देश में औसत से कम कीमत पर डंप किए जा रहे चीन के कई सामानों पर सरकार ने एंटी डंपिंग शुल्क भी लगाए हैं।

नीति का क्रियान्वयन की जरूरत : ट्राई चेयरमैन

कहा कि इस संकट के दौरान दूरसंचार क्षेत्र ने केंद्रीय भूमिका अदा की है। सीओएआई की बैठक को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि एनडीसीपी के क्रियान्वयन को तेज करने की जरूरत है। इसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला है जिसने कहा हो कि इस नीति में खामी है।

डी. पी. आभूषण को एनएसई के मुख्य बोर्ड पर स्थानांतरित एवं सूचीबद्ध करने हेतु निर्देशक मंडल की स्वीकृति

भोपाल • डी. पी. आभूषण लिमिटेड के निर्देशक मंडल की 29 जून को द्वितीय छमाही एवं संपूर्ण वित्तीय वर्ष, जिसकी समाप्ति 31 मार्च को हुई, के ऑडिटेड वित्तीय परिणाम पर विचार करने एवं अनुमोदित करने के लिए हुई तथा 03 जुलाई को एनएसई के एसएमएस प्लेटफॉर्म से



एनएसई के मुख्य प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित एवं सूचीबद्ध करने हेतु की गई, जिसे निर्देशक मंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। कंपनी का विक्रय एवं

कमाई 31 मार्च को समाप्त द्वितीय छमाही के लिए 470.09 करोड़ रुपये एवं 18.91 करोड़ क्रमशः रहा। कंपनी का विक्रय एवं कमाई 31 मार्च 2019 को समाप्त द्वितीय छमाही के लिए 493.22 करोड़ एवं 13.00 करोड़ रुपये क्रमशः था। इस प्रकार कंपनी के लाभ में लगभग 45 फीसदी की वृद्धि हुई है।

एनएफएल के द्वारा हाई-टेक मोबाइल सॉयल टेस्टिंग लैब्स लॉन्च किया

भोपाल • एनएफएल ने किसानों के घर के दरवाजे के सामने मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए पांच मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। एनएफएल के अध्यक्ष व्ही.एन.दत्त ने निदेशकों और अधिकारियों के साथ एनएफएल कॉर्पोरेट ऑफिस के परिसर, नोएडा में से एक ऐसी मोबाइल लैब को रवाना किया है। मृदा परीक्षण उपकरण से लदे इन मोबाइल लैब्स का उपयोग मिट्टी के पोषक तत्वों के विश्लेषण के लिए किया जाएगा। ये मोबाइल लैब किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए ऑडियो-वीडियो प्रणाली से भी लैस हैं।



कॉन्फेडरेशन ऑफ अन-एडेड एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री मप्र से की मांग

भोपाल • मप्र के कॉन्फेडरेशन ऑफ एडेड प्राइवेट स्कूल एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री मप्र से पालको द्वारा छात्रों की स्कूल फीस जमा करने की मांग की। आज पूरा देश एक भीषण संकट कोविड-19 की चपेट में है जिसमें देश का कोई भी क्षेत्र, कोई भी सेक्टर इस संकट से बचा हुआ नहीं है। प्रदेश के निजी विद्यालय भी इसी संकट से गुजर रहे हैं। इसके उपरान्त अधिकांश स्कूलों द्वारा लगातार ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से छात्रों की शिक्षण प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार पालको को छात्रों की फीस जमा करने के आदेश दिए गए हैं।



